

राहुल गाँधी की, फ्रैश, साफ छवि वाले जिलाध्यक्ष बनाने की योजना राजस्थान में क्यों फेल हो रही है

यह कार्यक्रम देश भर में जोर-शोर से आगे बढ़ रहा है, पर, राजस्थान में आकर फिसड़ी हो गया है

- रेणु मित्तल -
 - राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
 नई दिल्ली, 4 नवम्बर। राहुल गांधी ने संगठन सृजन अभियान शुरू कर साफ-सुथरी और प्रभावी राजनीति की दिशा में कदम बढ़ाया है। इस अभियान के तहत, जिलाध्यक्षों को अधिक अधिकार और मजबूती देने के लिए कुछ मानक और नियम तय किए गए हैं, ताकि संगठन के संचालन में ऊर्जा और प्रभावशीलता बनी रहे। यह प्रक्रिया पूरे देश के कई राज्यों में चल रही है।

इस कार्य के लिए पर्यवेक्षकों (ऑब्जर्वर्स) को नियुक्त किया गया है, जिन्हें राज्य नेतृत्व, प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) अध्यक्षों और अन्य स्वाधीन हितों को दरकिनार करते हुए, जिलाध्यक्षों के नामों की पैनल सूची तैयार करनी थी।

लेकिन राजस्थान में इन निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जा रहा है। केन्द्र से मिले स्पष्ट निर्देशों की

■ राजस्थान में यह दो व्यक्तियों के कारण असफल होता नज़र आ रहा है। प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा व प्रभारी रंधावा।

■ स्पष्ट निर्देश थे कि दिल्ली से पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे, जो खोजबीन व छानबीन के बाद, नए जिलाध्यक्षों के नाम प्रस्तावित करेंगे।

■ यह भी स्पष्ट निर्देश थे कि प्रदेशाध्यक्ष व राज प्रभारी की इन नियुक्तियों में कोई भूमिका नहीं होगी।

■ पर, प्रदेशाध्यक्ष व प्रभारी ने बारह नामों की सूची भेजी है। इस सूची में वे नाम शामिल हैं, जो काफी हद तक विवादित हैं, जैसे प्रमोद सिसोदिया चित्तौड़गढ़, शबनम गोदारा हनुमानगढ़ तथा पुष्पेंद्र भारद्वाज जयपुर। इस तरह के कई नाम हैं, जो पुराने नेताओं व खेमेबाजी में भी सक्रिय रहे हैं।

पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं।

बताया जा रहा है कि जिन लोगों के नाम सुझाए गए हैं, उनमें कई पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो कि स्वच्छ छवि और प्रभावी जिलाध्यक्षों की मूल भावना के खिलाफ हैं। रंधावा, जिन्हें राजस्थान का प्रभारी बनाए रखा गया है, किसी वेणुगोपाल के करीबी माने

जाते हैं, और वेणुगोपाल पार्टी में वास्तविक रूप से कांग्रेस अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं।

रंधावा, डोटासरा, अशोक गहलोत और सी.पी. जोशी के गुट से जुड़े हुए हैं। ये नेता अपने-अपने क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं और ऐसे (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एस आई भर्ती : अशोक गहलोत के पूर्व पी एस ओ को जमानत नहीं मिली

जयपुर, 4 नवंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पीएसओ रहे राजकुमार यादव सहित पांच आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। इसी के साथ अदालत ने पीएसओ के बेटे

■ हाई कोर्ट ने पीएसओ के पुत्र सहित नौ आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिये।

भरत यादव सहित नौ आरोपियों को राहत देते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस चंद्र प्रकाश श्रीमाली की एकलपीठ ने यह आदेश 14 आरोपियों की ओर से दायर जमानत याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने पेपर लीक गैंग के सदस्य विजय कुमार डामोर, पेपर हल करने वाले प्रवीण कुमार, सत्येन्द्र यादव, टेनी एसआई समेता कुमारी और (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भूमिहार बिहार में जनसंख्या का 2.9 प्रतिशत ही हैं

फिर एनडीए ने बत्तीस व महागठबंधन ने पंद्रह भूमिहार नेताओं को क्यों टिकट दिये हैं, विधानसभा चुनावों में

■ इस प्रश्न का जवाब है, बिहार के इतिहास में, ऐतिहासिक व सामाजिक जीवन में भूमिहार जाति का भारी प्रभाव रहा है।

■ भूमिहार मुख्य रूप से लैंड ओनिंग जाति हैं और कई छोटे-बड़े राजघरानों में, जैसे बेतिया, ठिकारी, हथुआ, तामुखी, श्योहर, पाकुर, महिषादल, महेशपुर व वाराणसी, भूमिहार ठिकाने हैं।

■ बिहार में भूमिहारों ने कई बुद्धिजीवी, जैसे, रामधारी सिंह दिनकर, राहुल सांस्कृतायन, रामवृक्ष बेनीपुरी भी दिये बिहार को।

■ राजनीतिक दृष्टि से बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, भूमिहर नेता कृष्ण सिन्हा (1946-61) थे, उनके लंबे राजनीतिक जीवन में कई प्रभावशाली भूमिहार नेता पनपे। जैसे, महेश प्रसाद सिन्हा, कैलाशपति मिश्रा, वर्तमान में सी.पी. ठाकुर, केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जम्मू-कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा तथा वर्तमान उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा।

■ बुद्धिजीवी लैंड ओनिंग जाति, राजनीति व प्रशासनिक बिहार में बहुत महत्व रखती हैं। वर्ष 1990 से 2025 तक, नीतीश-लालू युग में सत्ता जरूर इन दोनों के हर्ड-गिर्द रही, पर, प्रशासनिक पकड़, उच्च शिक्षा, मीडिया, प्रोफेशनल, जैसे कानून व मैडिसिन आदि में भूमिहार छाये रहे।

एनडीए का आंतरिक फीडबैक, पटना में भारी झटका लग सकता है

एनडीए के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि 2020 में भाजपा ने पटना की 14 में से 9 सीटें जीती थीं, इस बार 3 या 4 सीटें ही मिलेंगी

-जाल खंबाता-
 -राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
 नई दिल्ली, 4 नवंबर। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार समाप्त होने के साथ ही राजनीतिक पारा अपने चरम पर पहुंच गया है, जिससे सत्तारूढ़ एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर की संभावना बन गई है। जैसे-जैसे तत्वीर साफ हो रही है, शुरुआती जमीनी आकलन यह संकेत दे रहे हैं कि राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव संभव है, खासकर पटना जिले में, जो पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का गढ़ माना जाता रहा है।

एनडीए के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने आंतरिक फीडबैक का हवाला देते हुए माना कि राज्य के राजधानी क्षेत्र में भाजपा को अप्रत्याशित झटका लग सकता है। पटना जिले की कुल 14 विधानसभा सीटों में से, जहां 2020 के चुनाव में भाजपा ने 9 सीटें जीती थीं,

■ पटना में पहले चरण में मतदान होना है। नुकसान को भांपते हुए प्रधानमंत्री ने खुद पटना की चुनावी मुहिम संभाली और विशाल रोड शो के जरिए भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की, पर, अभी अनिश्चितता कायम है।

■ राजनैतिक जानकारों ने कहा कि यह बदलता रुख सत्ता विरोधी लहर, बेरोज़गारी की चिंता और महागठबंधन के बढ़ते प्रभाव की वजह से है।

■ इन हालात में भाजपा की नज़र में नीतीश का मोल बढ़ गया है, भाजपा में। माना जा रहा है कि तेजस्वी को हराने के लिए नीतीश की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है।

इस बार पार्टी को महज 3 से 4 सीटों पर ही जीत मिलने का अनुमान है। इसलिए 6 नवंबर को होने वाला पहला चरण पार्टी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, जिसने इस जिले में अपने संगठन और स्टार प्रचारकों की पूरी ताकत झोंक दी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से पटना में भाजपा की चुनावी मुहिम की कमान संभाली, विशाल रोड शो और जोशीली जनसभा के जरिए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। लेकिन इन जबरदस्त (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

7 देशों के डिप्लोमैट्स की टीम चुनाव देखने बिहार गई

“नो भाजपा” (भाजपा को जानो) मुहिम के तहत दो दिन के प्रवास में इन डिप्लोमैट्स ने भाजपा के चुनाव प्रचार को करीब से देखा

-जाल खंबाता-
 -राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
 नई दिल्ली, 4 नवम्बर। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा द्वारा शुरू की गई “नो बीजेपी” (भाजपा को जानो) पहल के तहत जापान, इंडोनेशिया, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, भूटान और दक्षिण अफ्रीका के भारत में स्थित दूतावासों के राजनयिक प्रतिनिधियों का एक दल 2-3 नवम्बर 2025 को बिहार का दौरा करने के लिए गया, ताकि वे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार और भारत की जीवंत लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में वास्तविक जानकारी प्राप्त कर सकें।

इस प्रतिनिधिमंडल ने अररिया में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सार्वजनिक रैली देखी, जहाँ उन्होंने चुनाव प्रचार के

पैसेंजर ट्रेन व मालगाड़ी की टक्कर में 7 की मौत

बिलासपुर, 04 नवंबर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मंगलवार को एक मेमू लोकल ट्रेन और मालगाड़ी में जबरदस्त टक्कर हो गयी, जिसमें सात यात्रियों की मौत हो गयी और कई अन्य घायल हो गये।

दुर्घटना बिलासपुर स्टेशन के पास शाम को करीब चार बजे हुयी जिसमें

■ बिलासपुर स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन खड़ी मालगाड़ी से टकराई।

मेमू ट्रेन खड़ी मालगाड़ी से टकरा गयी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मेमू का इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे और जिला प्रशासन की टीमों मौके पर पहुंच गयीं और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बारह राज्यों में एसआईआर का काम शुरू

नयी दिल्ली, 04 नवंबर। चुनाव आयोग ने कहा कि 12 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का काम शुरू हो गया है।

चुनाव आयोग की ओर से मंगलवार को बताया गया कि बिहार में

■ चुनाव आयोग ने मंगलवार को घोषणा की।

एसआईआर के सफल समापन के बाद, इस अभ्यास के दूसरे चरण में नौ राज्यों (छत्तीसगढ़ , गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) के लगभग 51 करोड़ मतदाता शामिल होंगे। इसमें तीन केन्द्र शासित प्रदेशों (अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप और पुद्दुचेरी) के 3.21 जिले और 1,843 विधानसभा क्षेत्र शामिल होंगे।

उन्होंने कहा कि इन 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के लिए (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

यदि तुम्हारी कोई निंदा करे तो भीतर ही भीतर प्रसन्न होओ, क्योंकि तुम्हारी निंदा करके वह तुम्हारे पाप अपने ऊपर ले रहा है।

—ब्रह्मानंद सरस्वती

अब सभ्यताओं का नहीं, अर्थ व्यवस्थाओं के बीच संघर्ष का दौर

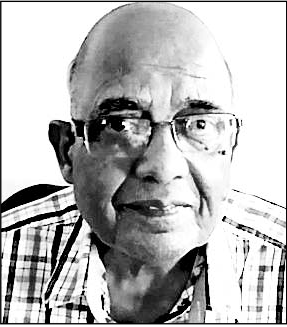
सूचना, तकनीक और पूंजी के आज के युग में वैश्विक राजनीति का चरित्र तेजी से बदल रहा है। कभी सभ्यताओं, धर्मों या साम्राज्यों के बीच युद्ध होते थे, परंतु 21^{वीं} सदी की दुनिया में यह पूरी तरह बदल रहा है। अब युद्ध हथियारों या विचारधाराओं का नहीं, बल्कि बाज़ार और मुद्रा के प्रभाव क्षेत्र का होने लगा है। अब सभ्यताओं का नहीं, अर्थव्यवस्थाओं के बीच संघर्ष होता है—जहां लक्ष्य भूमि नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक वर्चस्व है। आज किसी देश की ताकत उसके सैन्य हथियारों से भी बढ़कर उसके जीडीपी, औद्योगिक उत्पादन, स्टार्टअप इकोसिस्टम और तकनीकी प्रभुत्व से मापी जाती है। अब निवेश सम्मेलनों, व्यापार समझौतों और मुद्रा समझौतों से दुनिया के समीकरण तय होते हैं। आधुनिक कूटनीति अब आर्थिक हितों की रखवाली वाली बन चुकी है।यह स्पष्ट हो चुका है कि सभ्यताएं नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्थाएं ही वास्तविक शक्ति केंद्र हैं।

सोशियल संघ के पतन के बाद अमरीका अपने को अधिक सुरक्षित होने की अपेक्षा असुरक्षित महसूस कर रहा है और उसके राष्ट्रपति ट्रम्प अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने में लगे हैं ताकि दुनिया में अमरीका का वर्चस्व बना रहे। अमरीकी मुद्रा डॉलर सिर्फ भरोसे के बल पर टिकी है। इसे हर अर्थशास्त्री जानता है। मगर इसकी वैश्विक स्वीकार्यता है। डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी है। तेल और अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ज्यादातर डॉलर में होता है, इसलिए इस मुद्रा की मांग बहुत ऊंची बनी रहती है। मगर डॉलर ‘फिएट मनी’ है, यानी इसकी कीमत सरकार के भरोसे और आर्थिक नीतियों से तय होती है न कि किसी भौतिक आधार के जैसे सोना। अमेरिकी डॉलर को भरोसा मिलता है अमेरिका के वित्तीय प्रभुत्व, तथा वैश्विक व्यापार में उसकी भूमिका से। इसे बनाए रखने के लिए अमरीका हमेशा ऐसा प्रपंच रचता रहता है जिससे उसकी आर्थिक ताकत सुरक्षित रहे और डॉलर मजबूत बना रहे। सभी देख रहे हैं कि अमरीका अपने डॉलर के प्रभुत्व का राजनीतिक हथियार की तरह उपयोग करता रहा है। अमरिका किसी देश पर प्रतिबंध लगा कर उस देश की डॉलर लेन-देन प्रणाली को रोक सकता है। यह उसकी ताकत है। विश्व बाज़ार में डॉलर पर निर्भरता ऐतिहासिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों से है और दुनिया के देशों को व्यापार करते समय इन्हीं कारणों से डॉलर पर निर्भर रहना पड़ता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जुलाई 1944 में अमरीका में न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स स्थित माउंट वाशिंगटन होटल में संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जहां 44 देशों के प्रतिनिधियों ने ‘ब्रेटन वुड्स प्रणाली’ नामक एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था स्वीकार की। इस समझौते में तीसरी दुनिया की कोई भागीदारी नहीं थी क्योंकि वे देश तब ब्रिटेन के साम्राज्य के अधीन थे। विश्व युद्ध के कारण पूरा यूरोप ध्वस्त हो चुका था मगर अमरीका उस आंच से बचा रहा था। उस समय अमरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार था। इसलिए तय किया गया कि 1/35 औंस सोने का एक डॉलर होगा, और बाकी देश अपनी मुद्राओं को डॉलर से जोड़ेंगे। इस तरह डॉलर विश्व की रिजर्व करेंसी बन गया। बाद में 1970 के दशक में अमेरिका ने सऊदी अरब और अन्य तेल उत्पादक देशों से अपने निवेश की एवज में समझौता किया कि वे तेल की कीमत डॉलर में तय करेंगे। इससे दुनिया के हर देश को तेल खरीदने के लिए डॉलर की ज़रूरत पड़ने लगी। यह पेट्रोडॉलर सिस्टम कहलाया। इसने डॉलर की अंतरराष्ट्रीय मांग को स्थायी बना दिया। दुनिया के देश अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में राशि का निपटान डॉलर में करने लगे। अमेरिकी डॉलर 1/35 औंस सोने की स्थिर विनिमय दर पर परिवर्तनीय था। अमेरिका पर सोने की कीमत स्थिर रखने की जिम्मेदारी थी और भविष्य में सोने की परिवर्तनीयता में विश्वास बनाए रखने के लिए उसे डॉलर की आपूर्ति को समायोजित करना पड़ता था। ‘ब्रेटन वुड्स प्रणाली’ तब तक लागू रही जब तक कि लगातार अमेरिकी भुगतान असुलन घाटे के कारण डॉलर अमेरिकी सोने के भंडार से अधिक नहीं हो गए, जिसका अर्थ था कि संयुक्त राज्य अमेरिका आधिकारिक मूल्य पर सोने के बदले डॉलर को भुनाने के अपने दायित्व को पूरा नहीं कर पा रहा था। इसलिए अमरीका ने चतुराई की। राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने 1971 में डॉलर को सोने से पूरी तरह अलग कर दिया। उसके बाद डॉलर का मूल्य सोने से नहीं बल्कि अमेरिकी सरकार के भरोसे पर निर्भर हो गया। यह भरोसा अमरीका की आर्थ्यव्यवस्था की ताकत से बना हुआ है और इसीलिए उसकी वैश्विक स्वीकार्यता बनी हुई है।

अब जब विश्व में नई अर्थव्यवस्थाएं महत्वाकांक्षी रूप से उभरने लगी है, अमरीका अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए छटपटा रहा है। जिसके परिपेक्ष्य में उसके राष्ट्रपति ट्रम्प का व्यवहार समझा जा सकता है। कहते हैं प्यार और युद्ध में सब जायज होता है। ट्रम्प के लिए आर्थिक युद्ध में सब जायज है। उनके लिए अब तक बने वैश्विक नियमों का कोई महत्व नहीं है। वे अब अपनी शर्तों पर नयी वैश्विक अर्थ व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वे अपना आधिपत्य चाहते हैं। वह वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमरीकी साम्राज्यवाद चाहते हैं। एक चतुर व्यवसायी की तरह उन्हें लगता है को अमरीकी आर्थिक साम्राज्यवाद को असली चुनौती यूरोप से नहीं बल्कि एशिया से उभर रही भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं से मिलने वाली है। इस समय जो शतरंज जैसी चालें चली जा रही हैं उन्हें इसी परिपेक्ष्य में बेहतर समझा जा सकता है। इन हालात में जहां अमेरिका अपनी डॉलर आधारित अर्थव्यवस्था के वर्चस्व को बनाये रखने की जंग में लगा है। चीन ‘मेड इन चाइना’ से लेकर ‘मेड फॉर वर्ल्ड’ तक का सफर तय कर चुका है और अब वह अपनी मुद्रा युआन के अंतरराष्ट्रीयकरण के लिए प्रयत्नशील है। यूरोप यूरो मुद्रा के माध्यम से अपनी वैश्विक व्यापार की ताकत बनाए रखने की जद्दोजहद में लगा है। ऐसे माहौल में अपने आईटी सेवा क्षेत्र तथा 140 करोड़ की आबादी के बड़े बाज़ार के दम पर बढ़ती अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए भारत भी बड़ी महत्वाकांक्षा लिए उभर रहा है और अमरीकी के आर्थिक साम्राज्यवाद को चुनौति चुनौती दे रहा है। अमरीका द्वारा छेड़ा गया टैरिफ युद्ध की केवल व्यापारिक ही नहीं, बल्कि कूटनीतिक भी है। किंतु भारत जिस संयम, दूरदर्शिता और आत्मनिर्भर नीति के साथ इस संकट का सामना कर रहा है उसे अनेक विश्लेषक वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्पार्ट डिलोमेसी का एक उदाहरण मान रहे हैं। भारत का अमेरिका से आर-पार का व्यापारिक युद्ध छेड़ने से बचना जसकी कूटनीतिक जरूरत है, लेकिन उसने यह संदेश भी स्पष्ट रूप से जरूर दिया है कि वह किसी भी आर्थिक दबाव में झुकने वाला देश नहीं है और संवाद और पारस्परिक सम्मान से ही अमरीका के साथ व्यापारिक संबंध आगे बढ़ सकते हैं। कूटनीतिक संतुलन भारत की आर्थिक परिपक्वता का प्रामाण माना जा रहा है।

अर्थ व्यवस्थाओं की वैश्विक जंग के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने बहुआयामी रणनीति बनाई है जिसमें महंगे डॉलर रूपांतरणों से बचने के लिए एक सामान्तर गतिशील रुपया-रूबल विनिमय तंत्र विकसित करने, भुगतान पुष्टिकरण प्रणालियां स्थापित करने और वैकल्पिक वित्तीय प्लेटफ़ॉर्म तैयार करने की व्यवस्था है। आरबीआई ने पिछली 5 अगस्त को, अधिकृत डॉलर श्रेणी-1 बैंकों को पूर्व अनुमोदन के बिना अपने विदेशी सहयोगी बैंकों के लिए विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते खोलने की अनुमति दे दी। फिर 12 अगस्त को उसने नियमों में और ढील दी, जिससे वोस्ट्रो खातों में जमा धनराशि को सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों में स्वतंत्र रूप से निवेश करने की अनुमति मिल गई। वोस्ट्रो खाता एक घरेलू बैंक खाता होता है जो किसी विदेशी बैंक के लिए स्थानीय मुद्रा में खोला जाता है। विशेषज्ञों का कहना है, “वोस्ट्रो खाता रूस के साथ तेल व्यापार को सुगम बनायेगा क्योंकि यह लेनदेन को डॉलर जैसी तृतीय-पक्ष मुद्राओं के माध्यम से परिवर्तित किए बिना सीधे रुपये में निपटाने की सुविधा प्रदान करता है। तेल क्षेत्र में, रूसी निर्यातक इस व्यवस्था के तहत भारतीय बैंकों के वोस्ट्रो खातों में भारतीय रुपये रख सकते हैं, जिससे भारतीय आयातक डॉलर को दरकिनार करते हुए सीधे रुपये में भुगतान कर सकते हैं। यह व्यवस्था मुद्रा रूपांतरण लागत, विनिमय दर जोखिम और भुगतान में देरी को कम करेगी। रूसी संस्थाएं इस व्यवस्था से प्राप्त अतिरिक्त शुल्क शेष राशि को भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों, बॉन्ड, इक्विटी और व्यापारिक ढाँचा परियोजनाओं में भी निवेश कर सकेंगी। इसके अलावा, तीसरे देशों के निर्यात के लिए रुपया शेष राशि का उपयोग करने के भी प्रस्ताव हैं, जिससे रूसी आपूर्तिकर्ता अन्य मुद्राओं में भुगतान प्राप्त करते हुए भारतीय सामान खरीद सकेंगे। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात को शामिल करते हुए त्रिपक्षीय निपटान तंत्र पर भी बातचीत चल रही है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया, यूएई, यूरोपीय संघ, और आसियान देशों से मुक्त व्यापार समझौतों पर काम शुरू करके अपने निर्यात बाज़ारों का दायरा बढ़ाने का प्रयास किया है। इस नीति से भारत ने न केवल अपने निर्यातकों के लिए नयी राहें बनाई हैं, बल्कि अमरीकी टैरिफ के प्रभाव को भी काफी हद तक कम किया है। भारत ने अमरीका के साथ आर्थिक युद्ध में विवेक, आत्मनिर्भरता और कूटनीति की अपना हथियार बनाया है। यह खींचतान लंबे समय तक चल सकती है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि आने वाले सालों में आर्थिक प्रतिस्पर्धा का नया दौर शुरू हो सकता है। भारत का जनसांख्यिकीय लाभार्श उसका इस युद्ध में असली हथियार होगा। अब नया इतिहास अर्थशास्त्री और निवेशक लिखने वाले हैं जो मुद्रा को प्रभावी बनाने वाले योद्धाओं की कहानियां कहेंगे।"

—अतिथि संपादक, राजेन्द्र बोड़ा (वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)



डॉ. जे के गर्ग

गुरु नानक जी ने अपने अनुयायियों को दस उपदेश दिए जो कि सदैव प्रासंगिक बने रहेंगे। गुरु नानक जी की शिक्षा का मूल निचोड़ यही है कि परमात्मा एक, अनन्त, सर्वशक्तिमान और सत्य है। वह सर्वत्र व्याप्त है। मूर्ति-पूजा आदि निरर्थक है। नाम-स्मरण सर्वोपरि तत्व है और नाम गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। गुरु नानक की वाणी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से ओत-प्रोत है। उन्होंने अपने अनुयायियों को जीवन की दस शिक्षाएं दी जो इस प्रकार हैं।

ईश्वर एक है। ईश्वर सब जगह और प्राणी मात्र में मौजूद है। ईश्वर की भक्ति करने वालों को किसी का भय नहीं रहता। ईमानदारी से और मेहनत कर के उदरपूर्ति करनी चाहिए। बुरा कार्य करने के बारे में न सोचें और न किसी को सताएं। सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। ईश्वर से सदा अपने लिए क्षमा मांगनी चाहिए। मेहनत और ईमानदारी की कमाई में से जरूरतमंद को भी कुछ देना चाहिए। सभी स्त्री और पुरुष बराबर हैं। भोजन शरीर को जिंदा रखने के लिए जरूरी है पर लोभ-लालच व संग्रह वृत्ति बुरी है। सिख ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि गुरु नानक नित्य बेई नदी में स्नान करने जाया करते थे। एक दिन वे स्नान करने के पश्चात वन में अंतर्ध्यान हो गये। उस समय उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। परमात्मा ने उन्हें अमृत पिलाया और कहा- “ मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, जो तुम्हारे संपर्क में आयेगे वे भी

आनन्दित होंगे। जाओ दान दो, उपासना करो, स्वयं नाम लो और दूसरों से भी नाम स्मरण कराओ।” इस घटना के पश्चात वे अपने परिवार का भार अपने श्वसुर को सौंपकर विचरण करने निकल पड़े और धर्म का प्रचार करने लगे।

उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों के साथ ही विदेशों की भी यात्राएं की और जन सेवा का उपदेश दिया। बाद में वे करतारपुर में बस गये और 1521 ई. से 1539 ई. तक वहीं रहे। नानक देवजी ने 25 सितंबर, 1539 को अपना शरीर त्याग दिया था। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया जो बाद में गुरु अंगद देव के नामसे जाने गये। नानक देव जी ने कहा- “मोन धारण उनके नाम जपो, क्योंकि इसी से मानसिक आध्यात्मिक शक्ति मिलती है और आत्मिक शांति भी।”

सिख हमेशा अपनी आमदनी का दसवा हिस्सा दान-पुण्य में खर्च करे।

सच्चाई तो यही है कि गुरु नानक देवजी एक महान दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्मधारक, समाजसुधारक, कवि और देशभक्त थे। वे विश्वबंधुत्व में विश्वास करते थे और उनमें सच्ची मानवता के सभी गुण मौजूद थे। उनके बचपन के समय में कई चमत्कारिक घटनाएं घटी जिससे जन साधारण उन्हें दिव्य व्यक्तित्व का स्वामी मानते थे। नानकदेव जी वास्तव में आलोलिक श्रेणी के संत महापुरुष थे। गुरु नानक ने बचपन से ही रूढ़िवादिता के विरुद्ध संघर्ष करना शुरू कर दिया था। वे धर्मप्रचारकों को उनकी खाफियां बतलाने के लिए अनेक तीर्थ स्थानों पर पहुंचे और लोगों से धर्मांधता से दूर रहने का आग्रह किया। गुरु नानक जंयती पूरे देश में कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है जिसे प्रसाद वर्ष के रूप में मनाया जाता है। गुरुनानक सिखों के प्रथम गुरु हैं।

गुरु नानक देवजी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा, संवत् 1526 के दिन हुआ था। कुछ इतिहासकार एवं जानकार

गुरुनानक की जन्मतिथि 15 अप्रैल, 1469 मानते हैं। नानक जी का जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में खत्री कुल में हुआ था। तलवंडी का नाम आगे चलकर नानक के नाम पर ननकाना पड़ गया था। गुरु नानक देव के पिता और माता का का नाम मेहता कालू और तुत्तादेवी था। गुरु नानक को बचपन से ही सांसारिक विषयों में कोई रुचि नहीं थी और वे उनसे उनकी उससे विरक्ति थी। उनका अधिकांश समय आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग में व्यतीत होता था। गुरु नानकदेव महान सामाजिक सुधारक थे, उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी।

गुरु नानक जी का विवाह सन् 1487 में माता सुलखनी से हुआ। उनके दो पुत्र थे जिनका नाम श्रीचंद और लक्ष्मीचन्द था। नानक देव जी ने समाज में फैली कुरीतियों को खत्म करने के लिए अनेक यात्राएं की थी। ऐसा कहा जाता है कि नानक देव जी को उनके पिता ने एक बार व्यापार करने के लिए 20 रुपये दिए और कहा ‘इन 20 रुपये से सच्चा सौदा करके आओ।’ नानक देव जी सौदा करने निकले, रास्ते में उन्हें साधु-संतों की मंडली मिली। नानकदेव जी साधु-संतों को 20 रुपये का भोजन करवा कर वापस लौट आए। पिताजी ने पूछा- ‘क्या सौदा करके आए?’ उन्होंने कहा- ‘साधुओं ईश्वर की सीमाएं और कार्यक्षेत्र संपूर्ण मानव जाति को सोच से परे हैं। सत्य को जानना हर चीज से बड़ा है और उससे भी बड़ा है सच्चाई के साथ आपको मदद करता है। इसलिए हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिये। कर्म भूमि पर फल पाने के लिए कर्म सबको करना पड़ता है। ईश्वर तो सिर्फ लक़ीरें देते हैं पर रंग उनमे हमको ही भरना पड़ेगा है। ईश्वर की हजारी आँखें हैं और फिर भी एक भी आँख नहीं। ईश्वर के हजारों रूप हैं और फिर भी प्रभुजी निराकार हैं। आप जी भी बीज आज बोयेंगे, उसका फल आपको देर-सबर जरूर मिलेगा। जब हमारा शरीर मैला हो जाता है तो हम



पानी से उसे साफ़ कर लेते हैं। उसी तरह जब हमारा मन मैला हो जाये तो उसे ईश्वर के जाप और प्रेम द्वारा ही स्वच्छ किया जा सकता है। याद रखे कि भगवान के दरबार में सभी कर्मों का लेखा-जोखा रहता है। बिना गुरु के कुछ भी काम अधूरा होता है। धन को जेब तक ही रखें उसे हृदय में जगह न दें। जब धन को हृदय में जगह दी जाती है तो सुख शांति के स्थान पर लालच, भेदभाव और बुराइयों का जन्म होता है। धन के भंडार से परिपूर्ण प्रभुत्व वाले सम्राटों की तुलना में वो चींटी महान है जिसके मन में ईश्वर का निवास है। यदि लोग अपने धन का प्रयोग सिर्फ अपने लिए और खजाना भरने के लिए करते हैं तो वह शव की तरह है, लेकिन यदि वे इसे दूसरों के साथ इसे बांटने का निर्णय लेते हैं तो वह प्रभुजी पवित्र प्रसाद बन जाता है। जो व्यक्ति किसी का हक छीनता है उसे कमी भी सम्मान नहीं मिलता। इसलिए कभी किसी का हक़ नहीं छीनना चाहिये। जिन्होंने प्रेम किया है वो ही लोग परमात्मा को पा सकते हैं। नानक देव जी के अनुसार एक आँकार यानी ईश्वर एक है।

गुरु नानक जी की शिक्षा का मूल निचोड़ यही है कि परमात्मा एक, अनन्त, सर्वशक्तिमान और सत्य है। वह सर्वत्र व्याप्त है। मूर्ति-पूजा आदि निरर्थक है। नाम-स्मरण सर्वोपरि तत्त्व है और नाम गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। गुरु नानक की वाणी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से ओत-प्रोत है। उन्होंने अपने अनुयायियों को जीवन की दस शिक्षाएं दी जो इस प्रकार हैं- “ईश्वर एक है। ईश्वर सब जगह और प्राणी मात्र में मौजूद है। ईश्वर की भक्ति करने वालों को किसी का भय नहीं रहता। ईमानदारी से और मेहनत कर के उदरपूर्ति करनी चाहिए। बुरा कार्य करने के बारे में न सोचें और न किसी को सताएं। सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। ईश्वर से सदा अपने लिए क्षमा मांगनी चाहिए। मेहनत और ईमानदारी की कमाई में से जरूरतमंद को भी कुछ देना चाहिए। सभी स्त्री और पुरुष बराबर हैं। भोजन शरीर को जिंदा रखने के लिए जरूरी है पर लोभ-लालच व संग्रह वृत्ति बुरी है।”

—डॉ. जे. के. गर्ग, पूर्व संयुक्त निदेशक कॉलेज शिक्षा

स्पानइल मस्कुलर एट्रोफी: मरीजों के लिए किफायती दवा का रास्ता खुला

उच्च न्यायालय के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर से दवा के दाम में 97 प्रतिशत राहत



विकास आसावत

हाल ही में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने रिव्स दवा निर्माता रोश कंपनी द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें नैटको फार्मा को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली दवा रिस्टिप्लाम के जेनेरिक संस्करण बनाने और बेचने की अनुमति दी गई थी। इससे पूर्व इसी वर्ष मार्च में दिल्ली हाई कोर्ट की एकल पीठ ने नैटको फार्मा की रोश के रिस्टिप्लाम सम्बंधित पेटेंट की वैधता के समबन्ध में दी गयी दलील को पेटेंट एक्ट के अनुसार प्रथम दृष्टया तर्कपूर्ण माना और पेटेंट को पूर्व में उनके ही जीनस पेटेंट यौगिक का स्पष्ट जैव समस्थानिक संशोधन माना।

साथ ही कोर्ट ने किसी दुर्लभ

बीमारी के इलाज के लिए उपलब्ध एकमात्र दवा की आम जनता के लिए बहुत ही किफायती और प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपलब्धता को भी फैसले के लिए महत्वपूर्ण कारक माना था। बाद में डिवीजन बेंच ने भी इसी माह फैसला देते हुए एकल न्यायाधीश के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया।

उच्च न्यायालय की युगल पीठ के फैसले के बाद नैटको फार्मा ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि कंपनी ने रिस्टिप्लाम के जेनेरिक संस्करण को तुरत प्रभाव से व कोर्ट के समक्ष उसकी मंशा अनुरूप दवा को प्रति बोटल 15,900 में जारी करने का निर्णय लिया जो रोश फार्मा द्वारा एवरिस्टी (रिस्टिप्लाम) की प्रति बोतल कीमत लगभग 6 लाख से 97 प्रतिशत कम है। नैटको ने अपने पेटेंट एक्सेस प्रोग्राम के तहत कुछ अधिक जरूरतमंद मरीजों को इस मूल्य पर भी बूट देने की इच्छा जाहिर की है।

स्पानइल मस्कुलर एट्रोफी (एस.एम.ए.) मांसपेशियों से समबन्धित एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार है जो एसएमएन1 जीन की डिफेक्टिव प्रतियों के कारण होता है। व मोटर न्यूरॉन्स को प्रभावित करता है। मोटर न्यूरॉन्स मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में विशिष्ट तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जो चेहरे, बांहों, पैरों, छाती, गले और जीभ की गति को नियंत्रित करती हैं।

साथ ही बोलने, चलने, निगलने और साँस लेने के लिए प्रयुक्त

मांसपेशियों की गतिविधि को भी नियंत्रित करती है।

आमतौर पर रिपोर्ट की जाने वाली दुर्लभ बीमारियों (ऑर्फन डिजीज) में, लाइसीसोमल भंडारण विकार, गौचर रोग, पोम्पे रोग, फ़ैब्री रोग, स्पानइल मस्कुलर एट्रोफी आदि शामिल हैं। नेशनल रजिस्ट्री फॉर रेयर एंड अदर इन्हैरिटेड डिसऑर्डर्स में अब तक 18366 दुर्लभ विकार से ग्रसित मरीजों का पंजीकरण हुआ है जो निश्चित ही वास्तविक संख्या से कम है जबकि भारत में ही प्रति वर्ष लगभग 4,000 नवजात एस.एम.ए. डिसऑर्डर के साथ पैदा होते हैं।

एस.एम.ए. के संभव इलाज में नवीन उपचारों ने रोगियों के लिए दीर्घायु और जीवन की गुणवत्ता में सुधार का अवसर दिखाया है लेकिन दूर-सुदूर क्षेत्रों में विशेषज्ञों की अनुपलब्धता व ट्रीटमेंट का सामर्थ्य के बाहर होने के कारण बहुसंख्यक परिजनों के लिए चुनौतीपूर्ण है।

उक्त वर्णित रोग फार्मा के रिस्टिप्लाम के अतिरिक्त ज़ोल्लेन्समा – दो साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक बार दिया जाने वाला एकमात्र स्वीकृत जीन थेरेपी है जिसकी कीमत लगभग 16 करोड़ है, वहीं इक्वेजान नुसिनसैन (स्पिनराजा) भी एक विकल्प है जिसके प्रत्येक डोज की कीमत लगभग 87 लाख है, ही अनुमत उपलब्ध इलाज है।

भारत सरकार द्वारा तिरसट असाध्य रोगों के उत्कृष्टता केंद्रों में

उपचार के लिए प्रति रोगी 50 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता भी एस.एम.ए. के इलाज में नाकाफी है जो प्रति मरीज 16 करोड़ से अधिक हो सकती है। इस कमी को पूरा करने के लिए व दानदाताओं द्वारा स्वीच्छक दान की सुविधा प्रदान लिए सरकार ने पारदर्शी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म बनाया गया है। इस पोर्टल पर रोगियों से संबंधित जानकारी, रोग, उपचार की अनुमानित लागत और उपचार करने वाले संस्थानों के बैंक खातों का विवरण उपलब्ध है।

आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान भारत सरकार पेटेंट एक्ट में उल्लेखित प्रावधानों प्रयोग का करके दवा व सार्वजनिक स्वास्थ्य से सम्बंधित पेटेंट्स को इस्तेमाल कर या कंपल्सरी लाइसेंस प्रक्रिया में लाकर किफायती दवायों पर जेनेरिक दवा को जन उपलब्ध उपलब्ध कर सकती है। सांसद श्री हरीस बीरन भी राज्य सभा में भारत सरकार द्वारा प्राय 100 के अंतर्गत कानूनी बूट देकर जेनेरिक्स के निर्माण को बढ़ावा देने की बात कह चुके हैं।

कोर्ट का यह निर्णय बौद्धिक संपदा अधिकारों और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाने के न्यायपालिका के निरंतर प्रयास को दर्शाता है। भारत पहले ही यूकेएफटीए व इफटीए जैसे मुक्त व्यापार समझौते से डाटा एक्सचेंजसिबिटी को बाहर रखकर, सस्ती दवा तक आसान पहुंच और न्यूनतम समयावधि में जेनेरिक दवा

उपलब्ध कराने के प्रति अपनी नीति पर तटस्थता जाहिर कर चुका है। केंद्रीय औषधि मामलक नियंत्रण संगठन ने भी देश भर के औषधि नियामकों को दुर्लभ रोगों के इलाज के लिए दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की स्वीकृति प्रक्रिया में तेजी लाने व वे ऐसे सभी आवेदनों पर तीन महीने के भीतर कार्रवाई का निर्देश दिए हैं। यौक्त सार्वजनिक स्वास्थ्य मुख्य रूप से राज्य का विषय है इसलिए केंद्रीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सख्त निगरानी जरूरी है।

पेटेंट एक्ट द्वारा जन स्वास्थ्य सम्बंधित प्रदत शक्तियों का समय समय पर इष्टतम इस्तेमाल, जेनेरिक्स निर्माताओं के लिए विशेष क्षमता निर्माण कार्यक्रम, दुर्लभ रोगों की दवाओं के नमूनों के सरकारी प्रयोगशाला मूल्यांकन को प्राथमिकता, अंतर्राष्ट्रीय दवा निर्माताओं के साथ साझेदारी, अनुसंधान में अधिक निवेश, न्यायालय के जन स्वास्थ्य व दवा के पेटेंट से सम्बंधित निर्णयों की सख्त पालना, केंद्र व राज्य सरकारों के बीच योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बेहतर तालमेल, क्राउड फंडिंग के बारे में जागरूकता आदि कुछ ऐसे कदम है जो एस.एम.ए. पीडितों के लिए उपचार और उनके गरिमापूर्ण जीवन के लिए मील के पथर साबित होंगे।

—विकास आसावत, पेटेंट अटार्नी एवं एडवोकेट

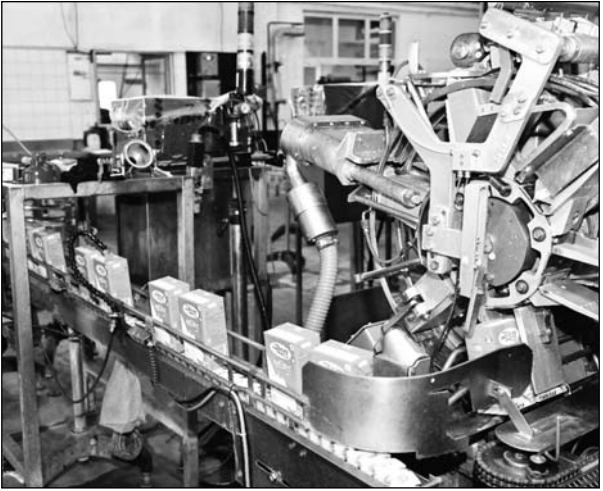
राजस्थान में डेयरी विकास के लिये 1००0 करोड़ रुपए का ‘‘कोरपस फण्ड’’ बनाने की मंजूरी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की इस ऐतिहासिक पहल से प्रदेश की सहकारी डेयरियों और उनसे जुड़े लाखों दुग्ध उत्पादकों को फायदा मिलेगा

—कार्यालय संवाददाता—

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राज्य सरकार ने डेयरी विकास के लिए राज्यभर की डेयरियों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च के लिये 1०00 करोड़ रुपये के “कोरपस फण्ड” बनाने की स्वीकृति जारी की है। यह स्वीकृति राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फण्ड के लिये जारी की गई है। डेयरी विकास के क्षेत्र में राजस्थान में पिछले दो दशकों में पहली बार यह ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की इस ऐतिहासिक पहल से प्रदेश की सहकारी डेयरियों और उनसे जुड़े लाखों दुग्ध उत्पादकों को फायदा होगा। साथ ही डेयरियों के आधारभूत ढांचे में विस्तार से आरसीडीएफ एवं जिला दुग्ध संघों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार की संभावनाएं तलाशने में भी मदद मिलेगी।

राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन की प्रशासक एवं प्रबन्ध संचालक श्रुति भारद्वाज ने बताया कि राजस्थान में डेयरी विकास के क्षेत्र में



इतनी बड़ी राशि के विनियोजन की स्वीकृति पहली बार जारी की गई है। स्वीकृत राशि से राज्यभर की सहकारी डेयरियों में दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता का विस्तार किया जायेगा और वर्तमान में आरसीडीएफ की कुल दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को 52 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 75 लाख लीटर प्रतिदिन किया

जावेगा। उन्होंने बताया कि अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर एवं सवाईमाधोपुर में नवीन एवं अत्याधुनिक तकनीक के डेयरी प्लान्ट्स की स्थापना की जावेगी। इसके साथ ही सीकर-झुन्झुनू, श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़, जोधपुर और कोटा दुग्ध संघों के डेयरी प्लान्ट्स का विस्तार एवं

- **राज्य सरकार के इस फैसले से आरसीडीएफ की दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता भी बढ़कर 75 लाख लीटर प्रतिदिन होगी**
- **इसके साथ ही पशु आहार उत्पादन क्षमता भी 2550 मैट्रिक टन प्रतिदिन हो जाएगी**

सुदृढीकरण किया जायेगा। कोटा, उदयपुर एवं राजसमंद जिलों में भी नये अत्याधुनिक संयंत्रों की स्थापना की जावेगी और जोधपुर पशु आहार संयंत्र का विस्तारीकरण किया जावेगा। पाली एवं हनुमानगढ़ जिले में 6० मैट्रिक टन क्षमता के नये डेयरी प्लान्ट्स भी स्थापित किये जाएंगे। श्रुति भारद्वाज ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत

इस बजट के कारण आरसीडीएफ के पशु आहार संयंत्रों की उत्पादन क्षमता भी बढ़ाई जा सकेगी।

वर्तमान में पशु आहार संयंत्रों की उत्पादन क्षमता 18०० मैट्रिक टन प्रतिदिन है, जिसे बढ़ाकर 25०0 मैट्रिक टन प्रतिदिन किया जाएगा। इसी प्रकार आरसीडीएफ के पाउडर प्लान्ट्स की वर्तमान क्षमता 165 मैट्रिक टन प्रतिदिन है, जिसे बढ़ाकर 225 मैट्रिक टन प्रतिदिन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि “कोरपस फण्ड” की 1० प्रतिशत राशि आरसीडीएफ स्वयं के द्वारा अर्जित लाभ में से देगा।

इसी प्रकार जिला दुग्ध संघों द्वारा भी कोरपस फण्ड की 1० प्रतिशत राशि उनके द्वारा अर्जित लाभ में से दी जावेगी। कोरपस फण्ड में बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं से उचित ब्याज दर पर ऋण लिया जा सकेगा।

केन्द्रीय प्रवर्तित योजना एचआईडीएफ के अन्तर्गत 3 प्रतिशत ब्याज की सब्सिडी भारत सरकार और 3 प्रतिशत ब्याज की सब्सिडी राजस्थान सरकार द्वारा दी जावेगी।

‘गिवअप’ अभियान से जुड़कर 4 2 लाख लोगों ने खाद्य सुरक्षा योजना से स्वयं नाम हटवाया

इस कारण राज्य सरकार 69.5० लाख नए पात्र लाभार्थियों को इस योजना से जोड़ सकी

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश में 42 लाख अग्रज लोगों ने स्वयं “गिव अप” अभियान से जुड़कर खाद्य सुरक्षा योजना छोड़ी है। इससे अब पात्र और वंचित लोगों को फायदा मिलेगा।

प्रदेश में जनसंख्या के अनुपात में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में लगभग 4.4६ करोड़ लाभार्थियों की सीमा निर्धारित है। परंतु यह सीमा पूर्ण हो जाने के कारण नए पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 1 नवम्बर 2०24 को आरंभ हुए “गिव अप”

अभियान में प्रदेशभर में 41.95 लाख से अधिक अपात्र लोगों द्वारा स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़कर सामाजिक उत्तरदायित्व का परिचय दिया है। करीब 27 लाख से अधिक व्यक्ति ई-केवाईसी नहीं करवाने के कारण स्वतः सूची से बाहर हो गए, जिससे नए पात्र लाभार्थियों के लिए स्थान उपलब्ध हुआ। यह अभियान अब जनआंदोलन का रूप ले चुका है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि 26 जनवरी को खाद्य सुरक्षा पोर्टल को पुनः शुरू किया। इसके बाद से अब तक लगभग 69.5० लाख नए

- **खाद्य सुरक्षा योजना में कलैक्टर्स जोड़ सकेंगे लाभार्थी, लोग स्वयं हटा सकेंगे अपना नाम सूची से**

पात्र लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पात्र वंचितों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अब जिला कलेक्टर को भी एनएफएसए सूची में नए लाभार्थियों को सम्मिलित

करने का अधिकार दिया गया है। साथ ही, सक्षम लाभार्थी पोर्टल के माध्यम से स्वयं अपना नाम सूची से हटवा सकते हैं। इससे पारदर्शिता और न्यायसंगतता सुनिश्चित हुई है।

मुख्यमंत्री की इस पहल से पात्र वंचितों को न केवल खाद्य सुरक्षा प्राप्त हो रही है, बल्कि उन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूँ, मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना में 45० रुपये की दर से प्रतिवर्ग 12 गैस सिलेंडर, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में 5 लाख रुपये का निशुल्क बीमा और

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में निशुल्क चिकित्सा सुविधा जैसी अन्य योजनाओं का लाभ भी प्राप्त हो रहा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी नीतियों के चलते राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का यह विस्तार न केवल राज्य की प्रशासनिक दक्षता का प्रमाण है, बल्कि सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और समान अवसर की भावना को साकार करने वाला ऐतिहासिक कदम है। राजस्थान सरकार की यह पहल ‘आपणे अग्रणी राजस्थान’ के संकल्प को मूर्त रूप दे रही है।

प्रदेश में चिकित्सा संस्थानों का आज से होगा सघन निरीक्षण

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल पर प्रदेशभर में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ किया जा रहा है। इसी कड़ी में चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवरसर के निर्देशों पर प्रदेशभर में 5 नवम्बर से 7 नवम्बर तक चिकित्सा संस्थानों का सघन निरीक्षण किया जाएगा। सघन निरीक्षण के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर चिकित्सा संस्थान में इर्षिडयन पब्लिक हेल्थ स्टैण्डर्ड पूरे हों, जिन संस्थानों में यह स्टैण्डर्ड पूरे नहीं होंगे, वहां मिशन मोड में इन स्टैण्डर्ड को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने मंगलवार को स्वास्थ्य भवन में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि 5 से 7 नवम्बर तक सभी संयुक्त निदेशक जोन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित अन्य अधिकारी अपने-अपने क्षेत्राधिकार में आते वाले सभी चिकित्सा संस्थानों का सघन निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। रिपोर्ट के आधार पर मानक पूरे नहीं करने वाले चिकित्सा संस्थानों में आवश्यक सुधार के लिए कदम उठाए जाएंगे।

प्रमुख शासन सचिव ने विभिन्न स्वास्थ्य मानकों की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी जिले हर हाल में टीकाकरण के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करें। उन्होंने निर्धारित लक्ष्य से पीछे रहने वाले सभी आरसीएचओ को 17 सीसीए के नोटिफ जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।

श्रीमती राठौड़ ने कहा कि प्रदेशभर में संचालित एम्बुलेंस सेवाओं का भी सघन निरीक्षण किया जाए, जहां भी एम्बुलेंस संचालन में कमियां पाई जा रही हैं, वहां नियमानुसार पैनल्टी लगाने के साथ ही आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में एम्बुलेंस सेवाओं का नियमित रूप से निरीक्षण करें। यह सुनिश्चित हो कि एम्बुलेंस संचालन योग्य हों, उनमें सभी जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध हों और क्रियाशील स्थिति में हों। उन्होंने बताया कि अप्रैल माह से अगस्त माह तक एम्बुलेंस सेवाओं के संचालन में कमियां पाई जाने पर 2 करोड़ रूपए से ज्यादा की पैनल्टी लगाई गई है।

देशभर से बैंक कर्मचारी नेता जयपुर में जुटेंगे

जयपुर । करीब 25 साल बाद ऑल इंडिया बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन (एआईबीईए)केन्द्रीय समिति की राष्ट्रीय बैठक की मेजबानी जयपुर में राजस्थान प्रदेश बैंक एम्पलाइज यूनियन करेगी। महासचिव महेश मिश्रा ने बताया कि इससे पहले सन् 2०0० में यह बैठक जयपुर में हुई थी। यह दो दिवसीय (5-6 नवम्बर) बैठक आज से एमआई रोड स्थित होटल गोल्डन टचयूलिएप में शुरू होगी। इसे एआईबीईए के राष्ट्रीय महासचिव सी एच वेंकटचलम संबोधित करेंगे। सम्मेलन में एआईबीईए के अध्यक्ष राजन नागर और सचिव बीएस रामबाबू के साथ कश्मीर से कन्याकुमारी तक देशभर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 1०5 से ज्यादा प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक से पूर्व मंगलवार को तारक भवन में राजस्थान प्रदेश बैंक एम्पलाइज यूनियन के महासचिव महेश मिश्रा के नेतृत्व में सम्मेलन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। इसमें आरपीबीईयू के चेयरमैन आरजी शर्मा और उप महासचिव सूरज भान सिंह अमेरा सचिव महेश शर्मा भी मौजूद रहे।

शिक्षा संकुल में कूडेदान की जगह का कार्याकल्प कर बनाया सभागार

जयपुर । शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने मंगलवार को डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल स्थित राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के कार्यालय में नवनिर्मित सभागार एवं लिफ्ट का लोकार्पण किया। इसका नाम “माधव सभागार” रखा गया है। सभागार की कुल क्षमता 4० लोगों के बैठने की है। इसके निर्माण पर 35 लाख रुपये खर्च हुए हैं। जिस जगह सभागार का निर्माण किया गया है, वहां पूर्व में कूड़ादान था, जिसे अभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त सभागार के रूप में परिवर्तित किया गया है। इससे पूर्व मंत्री मदन दिलावर ने भूतल पर नवनिर्मित एलीवेटर (लिफ्ट) का भी लोकार्पण किया। दिलावर ने बधाई देते हुए कहा कि, ये सभागार बहुत सुन्दर बना है, जो सभी प्रकार की बैठकें आयोजित करने के लिए उपयोगी साबित होगा। भवन में ऐसे लोग भी आते हैं जो सीढ़ियां चढ़ने में सक्षम नहीं होते हैं। ऐसे लोगों के लिए नवीन एलीवेटर (लिफ्ट) प्रारम्भ होने से बहुत लाभ होगा। लोग आसानी से भवन के सभी कक्षों में पहुंच सकेंगे। इस अवसर पर सभागार निर्माण में



शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने मंगलवार को डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल स्थित राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के कार्यालय में नवनिर्मित सभागार एवं लिफ्ट का लोकार्पण किया।

उल्लेखनीय कार्य करने वाले सुमित तिवारी, अधिशाषी अभियंता, समग्र शिक्षा, महाराजा सक्सेना, सहायक अभियंता, समग्र शिक्षा तथा ओपन स्कूल के सहायक निदेशक गिरिराज गुप्ता, बेसिक कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर आशिता शर्मा को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शासन सचिव शिक्षा

कृष्ण कुणाल, विशिष्ट शासन सचिव विश्व मोहन, निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीता राम , राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा एवं राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की निदेशक डॉ अनुपमा जोरवाल, निदेशक साक्षरता एवं सतत शिक्षा मनीष गोयल, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की सचिव डॉ. अरुणा शर्मा उपस्थित थे।

कृष्ण कुणाल, विशिष्ट शासन सचिव विश्व मोहन, निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीता राम , राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा एवं राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की निदेशक डॉ अनुपमा जोरवाल, निदेशक साक्षरता एवं सतत शिक्षा मनीष गोयल, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की सचिव डॉ. अरुणा शर्मा उपस्थित थे।

परिणामस्वरूप छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं हैं और नियमित कक्षाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। शिक्षक नहीं होने के कारण अनुसंधान कार्य भी बाधित हो रहा है, जिससे विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षणिक रैंकिंग तथा प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुंच रही है।

प्रो. अशोक कुमार ने कहा कि, राजस्थान विश्वविद्यालय का यह नकारात्मक रवैया

सोधे तौर पर राज्य के उच्च शिक्षा के भविष्य और हजारों छात्रों के करियर को खतरे में डाल रहा है। उन्होंने राज्यपाल से इस गंभीर

विषय पर तत्काल आवश्यक लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को शीघ्र उचित

कार्रवाई करने के निर्देशित करने का आग्रह किया है।

प्रो. अशोक कुमार ने कहा कि, राजस्थान विश्वविद्यालय का यह नकारात्मक रवैया

सोधे तौर पर राज्य के उच्च शिक्षा के भविष्य और हजारों छात्रों के करियर को खतरे में डाल रहा है। उन्होंने राज्यपाल से इस गंभीर

विषय पर तत्काल आवश्यक लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को शीघ्र उचित

कार्रवाई करने के निर्देशित करने का आग्रह किया है।

प्रो. अशोक कुमार ने कहा कि, राजस्थान विश्वविद्यालय का यह नकारात्मक रवैया

सोधे तौर पर राज्य के उच्च शिक्षा के भविष्य और हजारों छात्रों के करियर को खतरे में डाल रहा है। उन्होंने राज्यपाल से इस गंभीर

विषय पर तत्काल आवश्यक लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को शीघ्र उचित

कार्रवाई करने के निर्देशित करने का आग्रह किया है।

प्रो. अशोक कुमार ने कहा कि, राजस्थान विश्वविद्यालय का यह नकारात्मक रवैया

सोधे तौर पर राज्य के उच्च शिक्षा के भविष्य और हजारों छात्रों के करियर को खतरे में डाल रहा है। उन्होंने राज्यपाल से इस गंभीर

विषय पर तत्काल आवश्यक लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को शीघ्र उचित

कार्रवाई करने के निर्देशित करने का आग्रह किया है।

प्रो. अशोक कुमार ने कहा कि, राजस्थान विश्वविद्यालय का यह नकारात्मक रवैया

सोधे तौर पर राज्य के उच्च शिक्षा के भविष्य और हजारों छात्रों के करियर को खतरे में डाल रहा है। उन्होंने राज्यपाल से इस गंभीर

विषय पर तत्काल आवश्यक लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को शीघ्र उचित

कार्रवाई करने के निर्देशित करने का आग्रह किया है।

प्रो. अशोक कुमार ने कहा कि, राजस्थान विश्वविद्यालय का यह नकारात्मक रवैया

सोधे तौर पर राज्य के उच्च शिक्षा के भविष्य और हजारों छात्रों के करियर को खतरे में डाल रहा है। उन्होंने राज्यपाल से इस गंभीर

विषय पर तत्काल आवश्यक लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को शीघ्र उचित

कार्रवाई करने के निर्देशित करने का आग्रह किया है।

प्रो. अशोक कुमार ने कहा कि, राजस्थान विश्वविद्यालय का यह नकारात्मक रवैया

सोधे तौर पर राज्य के उच्च शिक्षा के भविष्य और हजारों छात्रों के करियर को खतरे में डाल रहा है। उन्होंने राज्यपाल से इस गंभीर

विषय पर तत्काल आवश्यक लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को शीघ्र उचित

कार्रवाई करने के निर्देशित करने का आग्रह किया है।

प्रो. अशोक कुमार ने कहा कि, राजस्थान विश्वविद्यालय का यह नकारात्मक रवैया

सोधे तौर पर राज्य के उच्च शिक्षा के भविष्य और हजारों छात्रों के करियर को खतरे में डाल रहा है। उन्होंने राज्यपाल से इस गंभीर

विषय पर तत्काल आवश्यक लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को शीघ्र उचित

कार्रवाई करने के निर्देशित करने का आग्रह किया है।

प्रो. अशोक कुमार ने कहा कि, राजस्थान विश्वविद्यालय का यह नकारात्मक रवैया

सोधे तौर पर राज्य के उच्च शिक्षा के भविष्य और हजारों छात्रों के करियर को खतरे में डाल रहा है। उन्होंने राज्यपाल से इस गंभीर

विषय पर तत्काल आवश्यक लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को शीघ्र उचित

कार्रवाई करने के निर्देशित करने का आग्रह किया है।

प्रो. अशोक कुमार ने कहा कि, राजस्थान विश्वविद्यालय का यह नकारात्मक रवैया

सोधे तौर पर राज्य के उच्च शिक्षा के भविष्य और हजारों छात्रों के करियर को खतरे में डाल रहा है। उन्होंने राज्यपाल से इस गंभीर

विषय पर तत्काल आवश्यक लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को शीघ्र उचित

कार्रवाई करने के निर्देशित करने का आग्रह किया है।

प्रो. अशोक कुमार ने कहा कि, राजस्थान विश्वविद्यालय का यह नकारात्मक रवैया

सोधे तौर पर राज्य के उच्च शिक्षा के भविष्य और हजारों छात्रों के करियर को खतरे में डाल रहा है। उन्होंने राज्यपाल से इस गंभीर

विषय पर तत्काल आवश्यक लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को शीघ्र उचित

कार्रवाई करने के निर्देशित करने का आग्रह किया है।

प्रो. अशोक कुमार ने कहा कि, राजस्थान विश्वविद्यालय का यह नकारात्मक रवैया

सोधे तौर पर राज्य के उच्च शिक्षा के भविष्य और हजारों छात्रों के करियर को खतरे में डाल रहा है। उन्होंने राज्यपाल से इस गंभीर

विषय पर तत्काल आवश्यक लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को शीघ्र उचित

कार्रवाई करने के निर्देशित करने का आग्रह किया है।

प्रो. अशोक कुमार ने कहा कि, राजस्थान विश्वविद्यालय का यह नकारात्मक रवैया

सोधे तौर पर राज्य के उच्च शिक्षा के भविष्य और हजारों छात्रों के करियर को खतरे में डाल रहा है। उन्होंने राज्यपाल से इस गंभीर

विषय पर तत्काल आवश्यक लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को शीघ्र उचित

कार्रवाई करने के निर्देशित करने का आग्रह किया है।

प्रो. अशोक कुमार ने कहा कि, राजस्थान विश्वविद्यालय का यह नकारात्मक रवैया

सोधे तौर पर राज्य के उच्च शिक्षा के भविष्य और हजारों छात्रों के करियर को खतरे में डाल रहा है। उन्होंने राज्यपाल से इस गंभीर

विषय पर तत्काल आवश्यक लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को शीघ्र उचित

कार्रवाई करने के निर्देशित करने का आग्रह किया है।

प्रो. अशोक कुमार ने कहा कि, राजस्थान विश्वविद्यालय का यह नकारात्मक रवैया

सोधे तौर पर राज्य के उच्च शिक्षा के भविष्य और हजारों छात्रों के करियर को खतरे में डाल रहा है। उन्होंने राज्यपाल से इस गंभीर

विषय पर तत्काल आवश्यक लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को शीघ्र उचित

कार्रवाई करने के निर्देशित करने का आग्रह किया है।

प्रो. अशोक कुमार ने कहा कि, राजस्थान विश्वविद्यालय का यह नकारात्मक रवैया

सोधे तौर पर राज्य के उच्च शिक्षा के भविष्य और हजारों छात्रों के करियर को खतरे में डाल रहा है। उन्होंने राज्यपाल से इस गंभीर

विषय पर तत्काल आवश्यक लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को शीघ्र उचित

कार्रवाई करने के निर्देशित करने का आग्रह किया है।

प्रो. अशोक कुमार ने कहा कि, राजस्थान विश्वविद्यालय का यह नकारात्मक रवैया

सोधे तौर पर राज्य के उच्च शिक्षा के भविष्य और हजारों छात्रों के करियर को खतरे में डाल रहा है। उन्होंने राज्यपाल से इस गंभीर

विषय पर तत्काल आवश्यक लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को शीघ्र उचित

कार्रवाई करने के निर्देशित करने का आग्रह किया है।

प्रो. अशोक कुमार ने कहा कि, राजस्थान विश्वविद्यालय का यह नकारात्मक रवैया

सोधे तौर पर राज्य के उच्च शिक्षा के भविष्य और हजारों छात्रों के करियर को खतरे में डाल रहा है। उन्होंने राज्यपाल से इस गंभीर

विषय पर तत्काल आवश्यक लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को शीघ्र उचित

कार्रवाई करने के निर्देशित करने का आग्रह किया है।

प्रो. अशोक कुमार ने कहा कि, राजस्थान विश्वविद्यालय का यह नकारात्मक रवैया

सोधे तौर पर राज्य के उच्च शिक्षा के भविष्य और हजारों छात्रों के करियर को खतरे में डाल रहा है। उन्होंने राज्यपाल से इस गंभीर

विषय पर तत्काल आवश्यक लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को शीघ्र उचित

कार्रवाई करने के निर्देशित करने का आग्रह किया है।

प्रो. अशोक कुमार ने कहा कि, राजस्थान विश्वविद्यालय का यह नकारात्मक रवैया

सोधे तौर पर राज्य के उच्च शिक्षा के भविष्य और हजारों छात्रों के करियर को खतरे में डाल रहा है। उन्होंने राज्यपाल से इस गंभीर

विषय पर तत्काल आवश्यक लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को शीघ्र उचित

कार्रवाई करने के निर्देशित करने का आग्रह किया है।

प्रो. अशोक कुमार ने कहा कि, राजस्थान विश्वविद्यालय का यह नकारात्मक रवैया

सोधे तौर पर राज्य के उच्च शिक्षा के भविष्य और हजारों छात्रों के करियर को खतरे में डाल रहा है। उन्होंने राज्यपाल से इस गंभीर

विषय पर तत्काल आवश्यक लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को शीघ्र उचित

कार्रवाई करने के निर्देशित करने का आग्रह किया है।

प्रो. अशोक कुमार ने कहा कि, राजस्थान विश्वविद्यालय का यह नकारात्मक रवैया

सोधे तौर पर राज्य के उच्च शिक्षा के भविष्य और हजारों छात्रों के करियर को खतरे में डाल रहा है। उन्होंने राज्यपाल से इस गंभीर

विषय पर तत्काल आवश्यक लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को शीघ्र उचित

कार्रवाई करने के निर्देशित करने का आग्रह किया है।

प्रो. अशोक कुमार ने कहा कि, राजस्थान विश्वविद्यालय का यह नकारात्मक रवैया

सोधे तौर पर राज्य के उच्च शिक्षा के भविष्य और हजारों छात्रों के करियर को खतरे में डाल रहा है। उन्होंने राज्यपाल से इस गंभीर

विषय पर तत्काल आवश्यक लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को शीघ्र उचित

कार्रवाई करने के निर्देशित करने का आग्रह किया है।

प्रो. अशोक कुमार ने कहा कि, राजस्थान विश्वविद्यालय का यह नकारात्मक रवैया

सोधे तौर पर राज्य के उच्च शिक्षा के भविष्य और हजारों छात्रों के करियर को खतरे में डाल रहा है। उन्होंने राज्यपाल से इस गंभीर

विषय पर तत्काल आवश्यक लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को शीघ्र उचित

कार्रवाई करने के निर्देशित करने का आग्रह किया है।

प्रो. अशोक कुमार ने कहा कि, राजस्थान विश्वविद्यालय का यह नकारात्मक रवैया

सोधे तौर पर राज्य के उच्च शिक्षा के भविष्य और हजारों छात्रों के करियर को खतरे में डाल रहा है। उन्होंने राज्यपाल से इस गंभीर

विषय पर तत्काल आवश्यक लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को शीघ्र उचित

तस्करी के दो आरोपियों को 2०-2० साल का कठोर कारावास

कोर्ट ने आरोपियों को दो-दो लाख रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया

भीलवाड़ा, (निसं)। विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस कोर्ट ने डोडा-चूरा तस्करी के मामले में दो आरोपियों को 2०-2० साल के कठोर कारावास और दो-दो लाख रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरूप गुर्जर ने बताया कि 7 नवम्बर 2०19 को काछोला थाना अधिकारी रतनलाल मय जांबा थाने से गश्त करते हुए लक्ष्मणगढ़ तिराहे पर नाकेबंदी कर वाहनों की जांच कर रहे थे। इस दौरान एक ट्रक आया जिसे शंका के आधार पर चेक किया तो ट्रक में 40 कट्टे अफीम डोडा-चूरा भरा हुआ मिला जो अजवाइन, प्याज और लहसुन के कट्टों के नीचे दबा कर रखा हुआ था। ट्रक चालक से नाम-मुछा तो ट्रक चालक ने अपना नाम मदनलाल पुत्र बालू लाल प्रजापत निवासी रायपुर और खलासी ने अपना नाम सांवरलाल पिता महावीर प्रसाद रायपुर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा होना बताया। पुलिस ने अफीम डोडा-चूरा का तोल किया तो कुल वजन 1०0० किलो पाया गया। मुलजिम्ओं को



पुलिस ने आरोपियों को विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस कोर्ट में पेश किया।

गिरफ्तार कर पुलिस ने चालान न्यायालय में पेश किया। ट्रायल पूरा होने के बाद विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस भीलवाड़ा जगदीश प्रसाद शर्मा ने मदनलाल और सवार को दोषी मानते हुए दोनों को 2०-2० साल के कठोर कारावास और दो-दो लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।

विशिष्ट लोग अभियोजक गुर्जर ने आरोप सिद्ध करने के लिए 7 गवाह और 2०2 दस्तावेज कोर्ट में पेश किए।

गेपसगार झील में कार व

बाइक गिरी : डूंगरपुर शहर में बादल

महल रिंग रोड पर सोमवार देर रात बाइक और कार के बीच टक्कर के बाद दोनों वाहन गेपसगार झील में गिर

गए। हादसे में बाइक सवार युवक की डूबने से मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त और कार सवार युवक को लोगों ने बचा लिया।

कोतवाली थाना पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान रोशन पुत्र भगवती शंकर हरसोत, निवासी पिंडावल के रूप में हुई है। वह डूंगरपुर

शहर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। रोशन अपने परिवार का इकलौता बेटा था और उसकी दो बहनें हैं। सोमवार शाम वह लाइब्रेरी में पढ़ाई करने गया था। इसके बाद अपने दोस्त अमन जैन के साथ बाइक से घर लौट रहा था। इसी दौरान गेपसागर झील के बादल महल रिंग रोड पर सामने से आ रही एक कार से टक्कर हो गई। हादसे के बाद बाइक और कार दोनों झील के पानी में जा गिरे। घटना के बाद रिंग रोड पर मौजूद लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और अमन जैन व कार सवार युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन रोशन गहरे पानी में डूब गया। बाद में गोताखोरों की मदद से शव बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को डूंगरपुर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। हादसे की खबर मिलते ही देर रात परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे, जहां उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया। पुलिस ने बताया कि हादसे की प्राथमिक वजह अंधेरा और तेज रफ्तार वाहन हो सकती है। मामले की जांच की जा रही है।

हेल्प डेस्क में शिक्षकों को मुक्त करने की मांग

बीकानेर, (निसं)। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने जिला कलेक्टर बीकानेर एवं विभागीय अधिकारी को ज्ञापन भेज कर आग्रह किया है की विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के हेल्प डेस्क कार्यक्रम में अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं को देखते हुए शिक्षकों को मुक्त रखा जाए।

संगठन के प्रदेश बरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि आचार्य ने ज्ञापन में अवगत करया कि वर्तमान में सरकार द्वारा समय से पूर्व परीक्षा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है जिस कारण से विद्यालयों में पाठ्यक्रम भी पूर्ण नहीं हो पाया है। शिक्षकों पर पाठ्यक्रम पूर्ण करवाने एवं फिर परीक्षाओं का संचालन नवंबर माह में ही करने का दबाव है। ऐसी स्थिति में एक ही समय में विशेष मतदाता पुनरीक्षण एवं विद्यालयी कार्यों के पूर्ण करने के दोहरे राजकीय दायित्वों को लेकर असमंजसता की स्थिति बन गई है। आचार्य ने ज्ञापन में बताया कि विशेष मतदाता पुनरीक्षण के अध्यक्ष का कार्य अन्य राजकीय कर्मचारियों के माध्यम से पूर्ण किया जा सकता है लेकिन परीक्षाओं का संचालन एवं पाठ्यक्रम पूर्ण करवाने का दायित्व केवल शिक्षक वर्ग ही पूर्ण कर सकता है। ऐसी स्थिति में शिक्षकों को विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम से मुक्त रखते हुए पाठ्यक्रम एवं परीक्षा संचालन की कार्यों के दायित्व को पूर्ण करने में ही रहने देना चाहिए। ज्ञापन में अवगत करवाया कि जारी आदेशों में अहता दिनांक 1 जनवरी 26 के तहत

- राज. शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने बीकानेर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन भेजा**

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत गठित होने वाली हेल्प डेस्क के लिए अधिकांश विद्यालयों में 2-2 बुथ होने के कारण एक विद्यालय से 6 शिक्षकों को लगाया गया है तथा जहां एक बुथ है वहां से 3 शिक्षकों को लगाया जाने से शिक्षण व्यवस्था प्रभावित होगी और साथ ही विद्यार्थियों के साथ न्याय नहीं होगा। वर्तमान में 2० नवंबर से राज्य के सभी विद्यालयों में राज्य स्तरीय समान परीक्षा योजना के तहत अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं का संचालन होना है। वहीं परीक्षाएं निर्धारित समय से पूर्व प्रारम्भ होने के कारण विद्यालयों में पाठ्यक्रम बकाया चल रहा है जिसे पूर्ण करवाने का दबाव भी शिक्षकों पर है। ज्ञापन में पाठ्यक्रम पूर्ण करने, परीक्षा समय एवं उसी बीच पुनरीक्षण कार्यक्रम की हेल्प डेस्क में शिक्षकों को लगाये जाने से शिक्षण व्यवस्था एवं परीक्षाएं प्रभावित होने की स्थिति रहेगी, जिससे बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं के सफल संचालन एवं अधूरे पाठ्यक्रम को पूर्ण करवाने हेतु छत्र हित में उक्त हेल्प डेस्क कार्यक्रम से शिक्षकों को मुक्त करवाने का आग्रह जिला कलेक्टर से किया गया है।

मानसिक रूप से कमजोर महिला ने फांसी लगाई

श्रीडूंगरगढ़, (निसं)। यहां एक मानसिक रूप से कमजोर महिला ने सुसाइड कर लिया। महिला ने शिवम मानव कल्याण सेवा संस्थान के कमरे में पछे से चुट्टी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। मृतका की पहचान 4० वर्षीय किरण पत्नी जितेंद्रसिंह निवासी सुडाबास, गोगामेडी, रतनगढ़ के रूप में हुई है। वह पिछले एक साल से

बिगाबास के वार्ड नंबर 24 में संचालित आश्रम में रह रही थी। सूचना मिलने पर डेड कॉन्स्टेबल रामचक्रप अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को नीचे उतारकर उपजिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। रामस्वरूप ने बताया कि मृतका के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

श्रीगंगानगर, (निसं)। पुरानी आबादी पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर शहर से चोरी हुई 5 मोटरसाइकिलें बरामद कीं। आरोपी मोटरसाइकिल चोरी के मामले में पहले भी गिरफ्तार हो चुका है।

एससुचन एं रजिस्टार ने बताया कि थाना इलाके से चोरी हो रही मोटरसाइकिलों की बरामदगी तथा आरोपी पकड़ने को एसपी डॉ. अमृता दुहन के निर्देश पर एसएसआई छिंद्रपालसिंह के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। टीम ने 8 बाई मोहनपुरा व हाल 6 ए निवासी 24 वर्षीय

इस संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से भामाशाह दिलीपराज कोठारी ने प्रेरक पुष्पराज बोहरा तथा रविंद्र सिंह बालावत के साथ जिला कलेक्टर डॉ प्रदीप के. गावड़े से मुलाकात कर नवीन भवन निर्माण के लिए प्रस्ताव प्रदान किया। जिला कलेक्टर ने कोठारी के इस निर्णय की सराहना करते हुए प्रसन्नता प्रकट की। जिला शिक्षा अधिकारी भंवरलाल परमार ने शिक्षा के क्षेत्र के विकास हेतु भामाशाह दिलीपराज कोठारी के महत्वपूर्ण निर्णय का स्वागत करते हुए आभार प्रकट किया।

रावला मंडी में राशन वितरण बाधित

रावला मंडी, (निसं)। उचित मूल्य की दुकानों पर राशन वितरण में बाधा आ रही है। सर्वर डाउन होने और ई-पोस मशीनों में स्टॉक अपडेट न होने के कारण उपभोक्ताओं को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। इससे स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। उपभोक्ताओं को राशन न मिल पाने का मुख्य कारण सर्वर की

खराबी और डीलरों की ई-पोस मशीनों में स्टॉक का अपडेट न होना है। गोदामों में राशन उपलब्ध होने के बावजूद, डीलरों के पास मशीन में जानकारी अपडेट न होने से वितरण रुक गया है। इसके अलावा, कुछ ई-पोस मशीनें आधार ई-केवाईसी पूरी न होने के कारण बंद पड़ी हैं।

जिला आपूर्ति अधिकारी से बात करने पर उन्होंने बताया कि यह समस्या सरकार द्वारा ई-पोस मशीन में सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण उत्पन्न हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस समस्या को जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा, ताकि उपभोक्ताओं को परेशानी न हो।

जिला आपूर्ति अधिकारी से बात करने पर उन्होंने बताया कि यह समस्या सरकार द्वारा ई-पोस मशीन में सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण उत्पन्न हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस समस्या को जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा, ताकि उपभोक्ताओं को परेशानी न हो।

जिला आपूर्ति अधिकारी से बात करने पर उन्होंने बताया कि यह समस्या सरकार द्वारा ई-पोस मशीन में सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण उत्पन्न हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस समस्या को जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा, ताकि उपभोक्ताओं को परेशानी न हो।

सम्मेलन में जाट समाज के 3० जोड़े परिणय सूत्र में बंधे



जाट समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन हरणी महादेव भीलवाड़ा में सम्पन्न हुआ।

भीलवाड़ा, (निसं)। सकल जाट समाज द्वारा राजस्थान मेवाड़ जाट महासभा, भीलवाड़ा के तत्वावधान में आयोजित जाट समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन हरणी महादेव भीलवाड़ा में सामाजिक एकता और सादगी का प्रदर्शन हुआ। इस अवसर पर 3० जोड़े परिणय सूत्र में बंधे, जिन्होंने एक नए और समृद्ध जीवन की शुरुआत की। कार्यक्रम में नव-दंपतियों को आशीर्वाद दिया। मुख्य अतिथियों में राजस्थान जाट महासभा प्रदेशाध्यक्ष राजाराम मील, सारिका सिंह चौधरी (प्रदेशाध्यक्ष, महिला काँग्रेस, राजस्थान), और अंकलेश जाखड़

शामिल रहे। अन्य विशिष्ट अतिथियों में भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी, नगर निगम महापौर राकेश पाठक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अदिति चौधरी, बदरी लाल जाट, महावीर चौधरी, एस.डी.एम. ओम प्रकाश माचरा, नगर निगम कमिश्नर हेमराम चौधरी, सीताराम चौधरी, हनुमान धायल (पुलिस निरीक्षक), देवीलाल चौधरी, राजवीर कुशवाह, होरा लाल भदाला, रामेश्वर जाट, प्रेमराम सियाग, गजराज चौधरी और जे.वी.पी. मीडिया ग्रुप चेयरमैन हरि राम किंवाड़ा मौजूद रहे। इस अवसर पर नवग्रह आश्रम के संस्थापक हंसराज चौधरी ने सभी

उपस्थित लोगों को नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया। जाट समाज के प्रमुखों और सदस्यों ने इस मंच से सामूहिक रूप से यह संकल्प लिया कि सामूहिक विवाह का यह आयोजन हर साल किया जाएगा, समाज के सभी लोग सामूहिक विवाह में ही अपने बच्चों की शादी करेंगे, शादियों में होने वाली होड़ा-होड़ी और फिजूलखर्ची (बर्बादी) से बचकर उस धन का उपयोग शिक्षा पर किया जाएगा। यह सामूहिक संकल्प समाज में एक नई दिशा देने और शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मंच संचालन नारायण भदाला ने किया।

श्रीगंगानगर जिले में डेंगू रोगियों का आंकड़ा दो सौ के करीब

श्रीगंगानगर, (निसं)। जिले में डेंगू रोगियों का आंकड़ा दोहरे शतक के करीब पहुंच रहा है। जिला अस्पताल में 4० सैपलों की एलाइजा जांच की गई। इनमें से पांच पॉजिटिव पाए गए हैं। अब जिला अस्पताल में भर्ती रोगियों की संख्या 22 हो गई है। नए मरीज तीन जिला मुख्यालय से, एक सादुलशहर और एक पदमपुर ब्लॉक एरिया का रहने वाला है। यह विभाग का आधिकारिक आंकड़ा है, लेकिन इसमें प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती मरीजों का आंकड़ा शामिल नहीं है। यहां तक कि तपोवन में हो रही एलाइजा जांच के आंकड़े भी शामिल नहीं हैं। तपोवन में 27 एलाइजा टेस्ट किए गए। इनमें 12 पॉजिटिव आए हैं। इनमें से तीन

श्रीगंगानगर जिले के हैं, शेष फाजिल्का और अबोहर तहसील के हैं। एक अक्टूबर से अब तक के डेटा की बात करें तो 3 नवंबर को आधिकारिक आंकड़ा 78 जबकि कुल आंकड़ा 81 पहुंच गया है। एक जनवरी से अब तक यह आंकड़ा 189 पहुंच चुका है। जिला अस्पताल की डीसी डॉ. ज्योत्सना चौधरी ने बताया कि अस्पताल में डेंगू वार्ड में अभी मरीज भर्ती करने को पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं। इसलिए वार्ड को नहीं बढ़ाया गया है। जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में एसडीपी बनाने की प्रक्रिया सही चल रही है और जरूरत के हिसाब से मरीजों को एसडीपी दिया जा रहा है। स्थिति

नियंत्रण में है और मरीज उपचार के बाद ठीक होकर घर लौट रहे हैं। अभी वार्ड में 22 मरीज उपचारार्थीन हैं।

जिला अस्पताल में मच्छरों की फौज पर नियंत्रण के लिए प्रयास शुरू नहीं किए गए। नगरपरिषद से मनरेगा मजदूर आए ही नहीं। लिहाजा सफाई का अभियान छेड़ा ही नहीं गया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार पीएमओ की ओर से 3० मजदूर मांगे गए थे, लेकिन एक भी नहीं आया। दोपहर में पता किया तो नगरपरिषद की ओर से बताया गया कि गलतफहमी के कारण मजदूर नहीं भेजे जा सके। अस्पताल के स्टाफ ने भी बताया कि मच्छरों के नियंत्रण के लिए प्रभावी प्रयास नहीं हो रहे।

लोगों को नेशनल हाइवे निर्माण के नाम पर बेघर किया

भीलवाड़ा, (निसं)। नेशनल हाइवे 158 की परियोजना निदेशक ने झुठा वादा कर मकान तोड़ दिया। 7०० मीटर के अधूरे हाइवे निर्माण की दुर्दशा ऐसी कि कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 158 मांडल आसीद रास को बनकर तैयार हुए 3 साल हो गए हैं, इस नेशनल हाइवे

- तोड़े गए मकान में लोग टेंट लगाकर रहने को मजबूर**



राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के नाम पर लोगों के घर तोड़ दिये।

रहने को मजबूर हो गए हैं। तीन साल में अधूरे हाइवे निर्माण और इस क्षतिग्रस्त हाइवे पर कई अधिकारी व राजनेताओं का गुजरना हुआ, निर्माण कार्य पूरा करने की बात पर परियोजना निदेशक राकेश कुमार से इन अधिकारियों राजनेताओं ने संपर्क किया तो हमेशा टालमटोल का जवाब मिला। सरकार की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी के आसीद सवाईभोज दौर

के दौरान भी परियोजना निदेशक को जमकर फटकार लगाई गई। कस्बे वासियों ने परियोजना निदेशक राकेश कुमार पर आरोप लगाए कि उनसे झुठा वादा कर उनके मकान तोड़ दिए गए।

विधायक जब्बर सिंह सांखला ने बताया कि परियोजना निदेशक की फोन लगाए गए लेकिन उन्होंने फोन उठाया ही नहीं।

बांसवाड़ा, (निसं)। राज्यपाल एवं

कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में “राष्ट्रीय एकात्मता : विविधता में एक चेतना” विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। उन्होंने संगोष्ठी के अंतर्गत जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन एवं अवलोकन करते हुए कहा कि राष्ट्र अनेक भाषा, संस्कृति, मतों, परंपराओं से मिलकर बनता है राष्ट्र की एक सीमा होती है। राष्ट्र में उस देश का नागरिक रहता है। कोई दूसरे देश का नागरिक आता है तो उसे उस देश की नागरिकता लेनी पड़ती है। संगठित जनसमुदाय, निश्चित भूभाग, संस्कृति, परंपरा, एकता की भावना हमें एक सूत्र में बांधती है। देश के नागरिकों में देश के मूल्यों, आदर्शों, मातृभूमि, समुदाय के प्रति निष्ठा और प्रेम होना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि एकता की भावना सिर्फ बातों में नहीं व्यक्ति के कर्मों में भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश जब बनता है तब एक देश से दूसरा देश



गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह को राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने संबोधित किया।

बन जाता है। कारण अलग-अलग होते हैं। बागडे ने कहा कि हमारे विघटन, हमारी गरीबी, हमारे एकसंघ नहीं होने का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने देश पर अतिक्रमण कर लिया। वह हमने अंग्रेजों से वापस लिया।

एक राष्ट्र विकसित बनता है जब नागरिक एकजुट होकर देशप्रेम के साथ अपना सर्वस्व अर्पण करते हैं। नागरिक अपनी शक्ति, बुद्धि, त्याग, आर्थिक स्वावलंबन से देश को विकसित बनाते हैं। उन्होंने कहा

कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से है। पहले गांव व कच्चे मकान होते थे जो अब पक्के बन गए हैं क्योंकि लोगों के पास पैसा आया है। देश की अर्थव्यवस्था का विकास हुआ

- राज्यपाल ने राष्ट्रीय एकात्मता विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया**

- राज्यपाल बागडे ने जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर आधारित प्रदर्शनी का किया अवलोकन**

है। उन्होंने कहा कि रामायण और महाभारत हमारी संस्कृति का मूल है। राम का नाम सभी भाषाओं में है। भजन-कीर्तन, व्याख्यान, भाषण, शिक्षण अलग-अलग भाषाओं में होता है मगर देवधर्म सबका एक ही है। एक ही गणेशजी की आरती अनेक भाषाओं में होती है मगर सबका भाव एक ही होता है। अनेक भाषा, खान-पान, वेशभूषा अलग-अलग होने के बावजूद हम सब एक हैं। हमारी संस्कृति भाषा अनेक भाव एक, पथ अनेक-गंतय एक की है।

